

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या :: 114/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/186

अपीलाण्ट्स :-	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :-
1. देवीसिंह जैतावत पुत्र श्री जालमसिंह जैतावत		1. रविन्द्र जैतावत पुत्र श्री देवीसिंह जैतावत
2. पदम कंवर पत्नी श्री देवीसिंह जैतावत निवासीगण - 77 राजेन्द्र नगर शारदा स्कूल के पास, पाली (राज.)		2. विनोद कंवर पत्नी श्री रविन्द्र जैतावत जातिगण राजपूत, निवासीगण - 77 राजेन्द्र नगर शारदा स्कूल के पास, पाली (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 16 माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थिति :- अपीलाण्ट स्वयं एवं उनके अधिवक्ता

--: निर्णय :-

दिनांक :- 10.11.2025

अपीलाण्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 16 माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 तहत विरुद्ध उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली के प्रकरण संख्या 9/2025 बअनवान देवीसिंह जैतावत बनाम रविन्द्र जैतावत वगैरह में आदेश दिनांक 31.07.2025 को निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है। अपीलाण्ट का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाण्ट की ओर से अपीलाण्ट स्वयं एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं रेस्पो. संख्या 01 एवं रेस्पो. संख्या को जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त होने के उपरान्त भी अपील अंतर्गत धारा 16 अधिनियम में वक्त बहस बार-बार आवाजे दिलवाये जाने के बाद पर अनुपस्थित रहे। वक्त बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील-मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट पाली के समक्ष माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4 एवं 23 के अन्तर्गत परिवाद इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि हम प्रार्थीगण वरिष्ठ नागरिक व काफी वृद्धावस्था में है। अपीलाण्ट संख्या 01 की उम्र 72 वर्ष व अपीलाण्ट संख्या 02 की उम्र 70 वर्ष है। अपीलाण्ट्स में आपस में पति-पत्नि का रिश्ता है जो आज भी कायम है दोनों अपीलाण्ट्स की काफी उम्र हो चुकी है तथा दोनों वरिष्ठ नागरिक एव वृद्ध है, न ही खाने-कमाने में सक्षम है। अपीलाण्ट संख्या 01 सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी है इस कारण अपीलाण्ट संख्या 01 को पेंशन प्राप्त होती है अपीलाण्ट्स केवल अपीलाण्ट संख्या 01 की पेंशन पर ही आश्रित है इसके अलावा अपीलाण्ट्स के आय का कोई स्रोत नहीं है। अपीलाण्ट्स, रेस्पोडेण्ट्स के साथ पता- 77,

राजेन्द्र नगर, शारदा स्कूल के पास, पाली (राज.) में निवास करते हैं। उक्त मकान अपीलाण्ट संख्या 01 ने अपनी स्वअर्जित आय से खरीदकर उक्त मकान का पट्टा अपने नाम से बनवाया था तथा उक्त मकान में रहवास हेतु बिजली-पानी का कनेक्शन भी अपीलाण्ट संख्या 01 ने अपने नाम से जारी करवाया था जिसका नियमित भुगतान भी अपीलाण्ट संख्या 01 द्वारा अपनी पेंशन में से किया जा रहा है। रेस्पोजेण्ट्स संख्या 02 अपीलाण्ट्स के उक्त रहवासीय मकान को हड़पने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। अपीलाण्ट संख्या 01 के घर से बाहर जाने के बाद उनकी पुत्रवधु उनके साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौच व मारपीट करती तथा धक्का देकर गिरा देती है। अपीलाण्ट्स के साथ मारपीट करने व उन्हे तंग व परेशान करने के कारण पुत्र व पुत्रवधु को उनके रहवासीय मकान से तुरन्त प्रभाव से बेदखल किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है अन्यथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण जीने के संवैधानिक अधिकार को नष्ट कर देंगे जो करने का अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार नहीं हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी नियमों व वृद्धगणों की भावना को मध्यनजर नहीं रखते हुए उक्त अधिनियम के कही विपरीत जाकर विधि-विरुद्ध आदेश पारित किया जो काबिले खारिज है। अतः जैर अपील स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करते हुए रेस्पोजेण्ट्स जो कि अपीलाण्ट के पुत्रवधु जो कि रेस्पोजेण्ट संख्या 02 है, को मकान से



के आदेश फरमावे।
श्रवणशुदा बहस व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके प्रकरण संख्या 09/2025 निर्णय दिनांक 31.07.2025 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर प्रकरण में यह प्रकट आया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट द्वारा वांछित राहत पर कोई वर्णन नहीं किया है न ही अपीलाण्ट द्वारा वर्णित किन्हीं तथ्यों का विवेचन किया है, न ही अपीलाण्ट द्वारा वांछित राहत के संबंध में किन्हीं कानूनी प्रावधानों को देखा है बल्कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाण्ट को भरण-पोषण हेतु प्रतिमाह पांच हजार की राशि रेस्पोजेण्ट्स को दिलवाये जाने का निर्णय किया है, जो कि प्रथम-दृष्ट्या ही आधारहीन, तर्कहीन, औचित्यहीन अविधिक है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.07.2025 अपास्त योग्य है।

निवा कलेक्टर, पाली

अब हम प्रकरण के तथ्यों पर विवेचन करना उचित समझते हैं। प्रकरण में मौलिक रूप से अपीलाण्ट द्वारा संबंधित कानून माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलाण्ट द्वारा अपनी पुत्रवधु रेस्पोजेण्ट्स संख्या 02 को उनके साथ अमानवीय एवं क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने के कारण पुत्रवधु अर्थात् रेस्पोजेण्ट्स संख्या 02 को उनके स्वयं के क्रयशुदा भूखण्ड/मकान से बेदखल करने की राहत चाही है। प्रकरण में यह सुस्थापित तथ्य है कि रेस्पोजेण्ट्स, अपीलाण्ट के पुत्र व पुत्रवधु है तथा वे अपीलाण्ट की अनुज्ञा से अपीलाण्ट के स्वयं क्रयशुदा भूखण्ड/मकान में रह सकते हैं। भारतीय सांस्कृतिक परम्पराओं में भी कोई बुजुर्ग अपने पुत्र, पुत्रवधु, पौत्र एवं पौत्रियों को विवाह के कई वर्षों बाद अपने घर से बेदखल करने की माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के विधिक प्रावधानों के तहत अनुज्ञा चाहता है, तथा उसके लिए वह

न्यायालय आता है तो यह तो कदापि नहीं माना जा सकता कि पुत्र एवं पुत्रवधु द्वारा अपने बुजुर्ग सास-ससुर (माता-पिता) की उचित सार-सम्भाल, सेवा सुश्रुषा, सदाशयता एवं मानवीयता का व्यवहार किया हो। कोई भी बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में अपने पुत्र एवं पुत्रवधु को अपने मकान से बेदखल करने के लिए तभी विवश होगा जबकि उसके साथ उसके पुत्र एवं पुत्रवधु द्वारा अत्यन्त कठोर व्यवहार किया जा रहा हो, क्योंकि कोई भी अकेला रहना उचित नहीं समझेगा। हस्तगत प्रकरण में जैर विवादित भवन का मालिक ससुर (अपीलाण्ट) है एवं उनकी पत्नी बीमार है तो इन परिस्थितियों में पुत्र एवं पुत्रवधु को सास-ससुर के मकान में जो कि उसके स्वयं का क्रयशुदा है, रखे जाने हेतु कोई विधिक अनुज्ञा दिया जाना उपादेय नहीं है। रेसपो. संख्या 01 व रेसपो. संख्या 02 अपीलाण्ट के पुत्र एवं पुत्रवधु होने के नाते वे अपने माता-पिता/सास-ससुर का उचित सार-सम्भाल नहीं कर अनुचित व्यवहार करने के उपरान्त बलात्, उनके मकान में रहे, यह पूर्णतया अन्याय होगा। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक सिद्धान्तों में निम्नानुसार प्रतिपादित किया है :-

1. **AIR 2022 Rajasthan 99 :-** Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act (56 of 2007), S.4, S.23, S.32 – Government of Rajasthan Maintenance of Parents and Senior Citizens Rules (2010), R.21 – Order of eviction – Protection of life and property of senior citizen – Son directed to vacate premises – Mother abused physically, mentally and socially by her son and daughter-in-law and deprived from living peacefully in her own house – Mother does not need any maintenance from her son, she is financially independent and has property in her name – Right of mother to live with dignity under art. 21 violated by acts of son – Being owner of disputed property and as per mandate of her husband's will, she has first right to live in disputed property in way she desires – Son along with his family directed to honor order of eviction. Constitution of India, Art. 21



↓
जिला कलेक्टर, बाली

2. **AIR 2018 BOMBAY 229 :-** Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act (56 of 2007), S.4 – Harassment to senior citizens – Tenement exclusively

owned by mother – Son, daughter-in-law and grand children beating, abusing and harassing mother – Order of eviction of son and his family, proper – No child can compel his parents to allow him and his family to stay with them.

3. **AIR Online 2024 UTR 478** :- Refusal to order eviction frustrated purpose of Act – Order of Tribunal was modified and eviction was ordered.
4. **AIR 2020 MADHYA PRADESH 51** :- Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act (56 of 2007), S.22, S.32 – Madhya Pradesh Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Rules (2009), R.19, R.20 – Protection of property of senior citizen – Eviction from property – Father-in-law claiming that ex-daughter-in-law and grandsons mentally tortured, harassed and assaulted him and threatened him with registration of false cases against him – Ex-daughter-in-law and grandson have no legal right to live in self acquired house of father-in-law – They are creating nuisance for father-in-law – He is not obliged to suffer their presence in his house – Order of eviction under Act, proper – Father-in-law cannot be dragged to file civil suit or eviction.
5. **2019 (2) DNJ (Raj.) 614** :- Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 – Secs. 2(b)(j), 4, 5, 6 – Tribunal has power and jurisdiction to make order of eviction – Act has overriding effect – Contention is not acceptable that the petitioner cannot be evicted from the house though it was self acquired property of respondent



↓
जिला कलेक्टर, पाली

Nos. 1 and 2 – Held, Order is not without jurisdiction and upheld.

उपरोक्त विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सभी न्यायिक नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है किया गया है कि 'Son and daughter-in-law cannot claim any right over the self acquired property of father and mother' अर्थात् किसी व्यक्ति के स्वयं के क्रयशुदा भूखण्ड अथवा मकान में उसके पुत्र एवं पुत्रवधु को औचित्यपूर्ण व्यवहार नहीं होने पर विधिक प्रावधानों के तहत बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त प्रेक्षणों के दृष्टिगत हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट पाली द्वारा अपने न्यायालय के प्रकरण संख्या 09/2025 बअनवान देवीसिंह जैतावत वगैरह बनाम रविन्द्र जैतावत वगैरह में पारित आदेश दिनांक 31.07.2025 को अपास्त करते हुए अपील-अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट के पुत्र एवं पुत्रवधु अर्थात् रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 को अपीलाण्ट के स्वयं के क्रयशुदा मकान संख्या 77 राजेन्द्र नगर शारदा स्कूल के पास पाली से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 को निर्देशित किया जाता है कि वे एक माह में अपीलाण्ट के स्वयं के क्रयशुदा मकान संख्या 77 राजेन्द्र नगर शारदा स्कूल के पास पाली को खाली कर कब्जा अपीलाण्ट को सुपुर्द करे। निर्णय दिनांक से एक माह की अवधि में रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 द्वारा अपीलाण्ट को उक्त मकान का कब्जा सुपुर्द नहीं किये जाने की स्थिति में थानाधिकारी, औद्योगिक नगर पाली जैर विवादित मकान अथवा भवन का विधिपूर्वक कब्जा करवाकर अपीलाण्ट को उसके क्रयशुदा भवन/मकान संख्या 77 राजेन्द्र नगर शारदा स्कूल के पास पाली का कब्जा सुपुर्द करावे। निर्णय की सत्यप्रति उभयपक्ष व पुत्रवधु, अर्थात् रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 को पालनार्थ भिजवाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय की सत्यप्रति के साथ लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

